

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2014/चैत्र 4, 1936	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 270
No. 43]	DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2014/CHAITRA 4, 1936	[N.C.T.D. No. 270

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 मार्च, 2014

सं.फा. 5(54)/पोलिसी/वैट/2013/पार्ट फा./1371-1383.— जबकि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को, वैट रिफंड की सुविधा प्रदान करने के लिये मालावी गणराज्य के उच्चायोग की सरकारी खरीद के पक्ष में साथ ही साथ राजनयिकों की अपनी व्यक्तिगत खरीद और नई दिल्ली में महात्मा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (एमजीआईईपी) को, वस्तुओं की खरीद के लिए क्रमशः पत्र संख्या डी-II/451/12(52)/2007 दिनांक 04-1-2014 और पत्र संख्या डी-II/451/16(1)/2010 दिनांक 11-1-2014 के द्वारा अनुरोध किया गया है।

और जबकि मैं, प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, यह मानता हूँ कि ऐसा करना जनसाधारण के हित में समीचीन है।

अब, इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 103 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्वारा उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता हूँ अर्थात्:-

संशोधन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की छठी अनुसूची में, प्रविष्टि संख्या 1 के भाग-क गणराज्यों की सूची में क्रम संख्या ए-144 के उपरांत तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सूची की प्रविष्टि में, क्रम संख्या बी-30 के उपरांत नई उप-प्रविष्टि सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :-

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या/टिन	गणराज्य/संगठन का नाम
"ए-145	07389914051	मालावी गणराज्य के उच्चायोग
बी-31	07899915468	महात्मा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (एमजीआईडीपी), नई दिल्ली ।"

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2014 से लागू होगी।

प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 25th March, 2014

No. F. 5(54)/Policy/VAT/2013/PF/1371-1383.— Whereas the Ministry of External Affairs, Government of India, has requested the Government of National Capital Territory of Delhi to grant facility of VAT exemption/refund to High Commission of the Republic of Malawi in favour of official purchases as well as personal purchases of its diplomats and Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP) in New Delhi on purchase of goods vide their letters No. D-II/451/12(52)/2007 dated 04-01-2014 and No.D-II/451/16(1)/2010 dated 11-01-2014 respectively :—

And, whereas, I, Prashant Goyal, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, am of the opinion that it is expedient in the public interest to do so.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), I hereby make the following amendments in the Sixth Schedule of the said Act namely:

AMENDMENTS

In the Sixth Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), in Entry No..1, in Part-A—List of Embassies, after entry A-144, and in Part-B—List of International Organisations, after entry B-30, the following entries shall be inserted, namely:—

Entry No.	Registration No./TIN	Embassy/Organisation Name
"A-145	07389914051	High Commission of the Republic of Malawi
B-31	07899915468	Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP), in New Delhi."

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2014.

PRASHANT GOYAL, Commissioner, Value Added Tax